>

Title : Need to provide basic facilities to the people living below poverty line in the country.

श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज): महोदया, योजना आयोग के गरीबी अनुमानों और मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या 6.52 करोड़ है। इन्हें ही सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है या कुछ अन्य सुविधा मुहैया करवाती है।

दूसरी ओर सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा बीपीएल की संख्या 37.2 करोड़ बताई गयी है, जिसे आयोग ने स्वीकार भी कर लिया है। जबकि वहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित एन.सी. सक्सेना समिति ने बीपीएल की संख्या देश में 50 फीसदी बताई है। उधर पांच वर्ष पहले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में बीपीएल की संख्या 60 फीसदी बतायी गयी थी।

सबसे रोचक बात यह है कि अर्जुन सेन गुप्त कमेटी ने ऐसे गरीबों की संख्या 77 प्रतिशत बताई है, जिनकी रोज की आमदनी 20 रूपये या उससे भी कम है। महंगाई के इस दौर में 20 रूपये में कोई व्यक्ति किस प्रकार भरपेट भोजन कर सकता है, यह समझ से परे है।

पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के जनपद इलाहाबाद के कुछ गांवों में भोजन की कमी के कारण कई बच्चों की मृत्यु तक हुई है।

मेरा आग्रह है कि सरकार अर्जुन सेन गुप्त कमेटी द्वारा बताए गए 77 प्रतिशत आबादी, जो 20 रूपये प्रतिदिन या उससे नीचे गुजर-बसर कर रही है, उसको भर पेट भोजन व अन्य सहुलियतें उपलब्ध करापने हेतु पर्याप्त कदम उठाना सुनिश्चित करे।